

पहले मुख्य समाचार।

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा— बीते नौ वर्षों में प्रदेश में आया बड़ा बदलाव, तीन गुना हुई राज्य की प्रति व्यक्ति आय।
- एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ भी की बातचीत।
- श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की चौदह घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस।
- उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने घोषित किया उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती दो हजार पचीस का अंतिम चयन परिणाम।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते नौ वर्षों में प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। कल लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन नौ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को तीन गुना करने में सफलता प्राप्त की है।

हमने नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तीन गुना करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय को तीन गुना करने में सफलता प्राप्त की। वीमेन वर्क फोर्स को प्रदेश के अंदर तीन गुना से अधिक उनकी उपस्थिति देश के अंदर शासकीय सेवा हो या फिर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कार्रवाई हुई है उनमें उनकी उपस्थिति वहां हुई है।

विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में कौशल विकास, रोजगार और उद्योगों से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ होगा।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने कल लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र-राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कल लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसवें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में दो सौ उन्नीस विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। इस दौरान उत्कृष्ट शिक्षकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों और स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नारायण प्रसाद को गवर्नर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए ने नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी। एक रिपोर्ट—
उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट नीट डॉट एनटीए डॉट एनआईसी डॉट इन पर अपने आवेदन नंबर से लॉग इन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और दो सौ रुपये के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा पन्द्रह जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करने के उद्देश्य से कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दोनों पक्षों की बैठक हुई। बैठक में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के साथ संबंधित पक्षकार भी मौजूद रहे। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी विवाद का अंतिम समाधान न्यायालय के निर्णय से ही संभव है।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एंटी करप्शन कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की चौदह घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। पुलिस की टीम आज उनकी कस्टडी लेकर पूछताछ करेगी। वहीं आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर कल अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया। अयोध्या विकास प्राधिकरण में ओएसडी महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें पंद्रह जुलाई तक मानचित्र व अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि निर्धारित समय तक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इनकी पत्नी सुप्रिया जी हैं। उनके द्वारा एक निर्माण किया गया है और उस निर्माण का नक्शा हमारे यहां से स्वीकृत नहीं है। इसीलिए जब चालानी कार्रवाई प्रस्तुत की गई है जी आई के द्वारा तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई। पहली नोटिस पर वो उपस्थित नहीं हुई। इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई जिसमें 15 तारीख नियत है। अब यह प्रोसिडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है, उसकी प्रोसिडिंग अगली कार्रवाई जाएगी।

प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने सभी प्राधिकरण और विभागों को ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीनें चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। कल इस संबंध में हुई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और सतत परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों के साझा प्रयासों से प्रदेश में आधुनिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जाए।

प्रदेश में टीबी उन्मूलन की प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स गोरखपुर में कल एक टेक्निकल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में पद्म श्री डॉ राजेंद्र प्रसाद सहित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े देश भर के साठ से अधिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। वर्चुअल माध्यम से कॉन्क्लेव को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी, साझेदारी और जन भागीदारी प्रदेश की टीबी उन्मूलन यात्रा के मूल आधार हैं। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग का कार्य नहीं, बल्कि पूरे समाज और विकास से जुड़ा साझा लक्ष्य है। एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक डॉ विभा दत्ता ने कहा कि एम्स गोरखपुर टीबी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार के साथ पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है।

प्रदेश सरकार ने 'बेड एण्ड ब्रेक फास्ट और होमस्टे नीति-दो हजार पचीस' में हितधारकों को सुविधाएं देने के लिए इसके प्राविधानों में संशोधन किये हैं। एक रिपोर्ट-

एसओपी संशोधन के अनुसार अब होम स्टे प्रतिष्ठान में कम से कम 01 और अधिकतम 08 कमरे पंजीकृत कराये जा सकते हैं। 09 कमरों से अधिक भवन वाली इकाईयाँ इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 16 बिस्तरों वाली डारमेट्री भी इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र इकाई मानी जायेगी। उन्होंने बताया कि ऑटो रिन्यूवल पंजीकरण समाप्ति की तिथि से तीन माह पहले पोर्टल पर कराया जा सकेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नती बोर्ड ने कल उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती दो हजार पचीस का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की सूची भर्ती बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गयी है।
